



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 1986/पौष 3, 1908

No. 617]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 1986/PAUSA 3, 1908

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

सं. 468/86—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 1315 (अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-
शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
की अधिसूचना सं. 332/86—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 जून,
1986 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) प्रारम्भिक भाग के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्न-
लिखित परन्तुक प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह तब जबकि ऐसी ईंधन-इस मीटर कारों का विनि-
र्माण, उद्योग मंत्रालय द्वारा और उद्योग मंत्रालय के तकनीकी
विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सहायकार द्वारा सम्यक

रूप से अनुमोदित समर्जित विनिर्माण कार्यक्रम के अधीन किया
जाता है और आयातकर्ता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के
औद्योगिक सहायकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए
जाने के लिए प्रेषित देशीकरण की डिग्री और पूर्ववर्ती वित्तीय
वर्ष में प्राप्त देशीकरण की वास्तविक डिग्री का विस्तृत ब्यौरा
दिलाने वाले प्रमाणपत्र पेश करता है और किसी ऐसे
माध्यम में जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की
डिग्री उस डिग्री से निम्न है जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित
की गई है वहां आयातकर्ता, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास
विभाग) के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी से
प्रमाणपत्र भी पेश करता है जिसमें यह प्रमाणित किया गया
हो कि देशीकरण की अपेक्षित डिग्री को प्राप्त करने में
असफलता विधिमान्य कारणों की वजह से है जो उसमें लेखबद्ध
किए जाएंगे और ऐसी असफलता न्यूनतम है।”;

(ख) स्पष्टीकरण,—

(i) खण्ड (iii) में,

(क) “तदनुसार प्रमाणित करता है” शब्दों के पश्चात् “(इस संबंध
में दिए गए प्रमाणपत्र को इनमें इनमें परन्तु ईंधन वस्तुता
प्रमाणपत्र कहा गया है)” कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

- (ख) "या पुणे (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय स्वशासित यंत्र मनुसंधान संगम" शब्द और कोष्ठकों का खोल किया जाएगा;
- (ii) खण्ड (ख) के अन्त में आने वाले "और" शब्द का खोल किया जाएगा और खण्ड (ग) के अन्त में निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- "(घ) ईंधन दक्षता परीक्षण, उत्पादन संयंत्र में परीक्षण, यंत्रिकी द्वारा सहसा की गई पांच मोटर कारों पर किया जाएगा और परीक्षण अंकों में से न्यूनतम अंक, ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने के प्रयोजन के लिए सुचयन होगा।"
- (ग) अन्त में निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"2. इस प्रकार दिया गया ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिवत होगा।

3. जहां आयातकर्ता इस अधिवृत्त के अधीन छूट का इस्तेमाल है किन्तु आयात के समय ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र पैरा करने में समर्थ नहीं है बल्कि ऐसा आयातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को यह बचनबद्ध करेगा कि वह ऐसा ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र आठ सप्ताह की अवधि के भीतर या बार सप्ताह से अधिक और बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा अधिवृत्त की जाए, पैरा करेगा तथा वह इसमें अन्तर्लिखित छूट के न दिए जाने की दशा में उद्बुद्धीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संवत् शुल्क के बीच के अंतर का संवाय करने का भी बचनबद्ध उस दशा में करेगा जब वह उक्त अवधि के भीतर ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र पैरा करने में असफल रहता है।"

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th December, 1986

NOTIFICATION

No. 468/86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1315 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 1 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 332/86-Central Excises, dated the 2nd June, 1986, namely:—

In the said notification,—

- (a) after the opening portion and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that such fuel efficient motor cars are manufactured under a phased manufacturing programme duly approved by the Ministry of Industry and the Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development in the Ministry of Industry and the manufacture produces a certificate from the Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development showing the details of the degree of indigenisation required to be

achieved under the aforesaid programme and the actual degree of indigenisation achieved in the preceding financial year and in a case where the degree of indigenisation achieved in the preceding financial year is lower than the degree as per the approved programme, the manufacturer also produces a certificate from an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) certifying that the failure in achieving the required degree of indigenisation is on account of valid reasons to be recorded in writing and that such failure is marginal;

(b) in the Explanation,—

(i) in clause (iii),—

(a) after the words and brackets "(Industrial Development)", the brackets and words "(certificate issued in this regard, hereinafter referred to as the fuel efficiency certificate)" shall be inserted;

(b) the words and brackets "or the Automotive Research Association of India, Pune (Maharashtra)" shall be omitted;

(ii) in clause (b), the words "and" occurring at the end shall be omitted and after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

(d) the fuel-efficiency test shall be conducted on five motor cars selected at random by the testing agency from the production plant and the lowest of the test figures shall be relevant for the purpose of issuing fuel efficiency certificate."

(c) the following paragraphs shall be inserted at the end, namely:—

"2. The fuel-efficiency certificate so issued shall be valid for a period of six months from the date of issue.

3. Where a manufacturer is entitled for exemption under this notification but is not able to produce a fuel-efficiency certificate at the time of clearance such manufacturer shall undertake to the Assistant Collector of Central Excise that he will produce such fuel-efficiency certificate within a period of eight weeks or such further extended period not exceeding four weeks as may be determined by the Collector of Central Excise and also undertake to pay an amount equal to the difference between the duty leviable but for the exemption contained herein and that already paid at the time of clearance, if he fails to produce the fuel efficiency certificate within the said period."

[F. No. 346/89/86-TRU]

प्रधिवृत्तना

सं. 469/86—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं. का. नि. 1316 (घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रमुखी के शीर्ष संख्यांक 87.03 के अंतर्गत आने वाले 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता के ईंधन-दक्ष मोटर कारों को, उक्त प्रमुखी में निविष्ट उक्त पर उद्घृष्टनीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उनके मूल्य के पच्चीस प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है :—

परन्तु यह तब जबकि ऐसी ईंधन-दक्ष मोटर कारों का निर्माण, उद्योग मंत्रालय द्वारा और उद्योग मंत्रालय के तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्पन्न से अनुमोदित संबंधित निर्माण कार्यक्रम के अधीन किया जाता है और आयातकर्ता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित देशीकरण की डिग्री और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की वास्तविक डिग्री का विस्तृत व्योम दर्शाते वाया प्रमाणपत्र पेश करता है और किसी ऐसे मामले में जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की डिग्री उक्त डिग्री से निम्न है जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित की गई है वहां आयातकर्ता, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संयुक्त सचिव से प्रतिभूति के अधिकारी से प्रमाणपत्र भी पेश करना है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि देशीकरण को अपेक्षित डिग्री का प्राप्त करने में असफलता विधिवान्य कारणों की वजह से है जो उसमें लेखबद्ध किए जाएंगे और ऐसी असफलता न्यूनतम है।

स्पष्टीकरण—इस अधिवृत्तना के प्रयोजनों के लिए, “1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कार” से ऐसी मोटर कार अभिप्रेत है जिसके बारे में प्रहसनगर (महाराष्ट्र) स्थित राजा मंत्रालय के मान अनुसंधान विकास स्थापन द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईंधन-दक्षता परीक्षण कहा गया है) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विभाग) के संयुक्त सचिव से प्रतिभूति के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है (इस संबंध में दिए गए प्रमाणपत्र की इसमें इसके पश्चात् ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र कहा गया है) कि ऐसी मोटर कार—

- (i) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 17 किलोमीटर चलेगी ;
- (ii) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 15 किलोमीटर चलेगी ;

ऐसा करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्—

(क) ईंधन-दक्षता परीक्षण—

- (i) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में 375 किलोग्राम आय-भार से किया जाएगा, और
- (ii) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, 450 किलोग्राम आय-भार से किया जाएगा ;

(ख) ईंधन-दक्षता परीक्षण ऐसे पेट्रोल का प्रयोग करते किया जाएगा जिसका ऑक्टैण लेवल 87 से अधिक नहीं है ;

(ग) ईंधन-दक्षता परीक्षण किसी बिगिष्ट लेवल परीक्षण पर पर कम से कम एक किलोमीटर दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अपरिवर्ती गति से किया जाएगा और परीक्षण करने के लिए प्रसिद्ध 20 चक्कर लगाए जाएंगे जिनमें से 10 चक्कर प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण श्रृंखला समुद्र तल की ऊंचाई तक और +25° से. परिवेश ताप के आधार पर संगणित किए जाएंगे ;

(घ) ईंधन-दक्षता परीक्षण, उत्पादन संबंध से परीक्षण अधिकारी द्वारा सहसा चुनी गई पांच मोटर कारों पर किया जाएगा और परीक्षण श्रृंखला में से न्यूनतम श्रेष्ठ ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा।

2. इस प्रकार दिया गया ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिवान्य होगा।

3. यहां आयातकर्ता इस अधिवृत्तना के अधीन छूट का हकदार है किन्तु आयात के समय ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में नहीं है वहां ऐसा आयातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को यह बताना करेगा कि वह ऐसा ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र प्राप्त सप्ताह की अवधि के भीतर या बार सप्ताह से अधिक और बराबर गई ऐसी अवधि के भीतर जो सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा प्रबंधित की जाए, पेश करेगा तथा वह इसमें अंतर्लिखित छूट के न किए जाने की दशा में उद्घृष्टनीय शुल्क और आयात के समय पहले ही सदल शुल्क के बीच का अंतर का संतान करेगा जो वजनबंध उस दशा में करेगा जब वह उक्त अवधि के आधार ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहता है।

4. यह अधिवृत्तना 31 दिसम्बर, 1983 तक, जितना यह तारीख को सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

NOTIFICATION

No. 469/86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1316(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fuel-efficient motor cars of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres, falling under heading No. 87.03 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from so much of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of twenty-five per cent ad valorem:

Provided that such fuel-efficient motor cars are manufactured under a phased manufacturing programme duly approved by the Ministry of Industry and the Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development in the Ministry of Industry and the manufacturer produces a certificate from the Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development showing the details of the degree of indigenisation required to be achieved under the aforesaid programme and the actual degree of indigenisation achieved in the preceding financial year and in a case where the degree of indigenisation achieved in the preceding financial year is lower than the degree as per the approved programme, the manufacturer also produces a certificate from an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) certifying that the failure in achieving the required degree of indigenisation is on account of valid reasons to be recorded in writing and that such failure is marginal.

Explanation.—For the purposes of this notification, “fuel-efficient motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres” means a motor car which is certified to run—

- (i) not less than 17 kilometres per litre of petrol in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres but not exceeding 1400 cubic centimetres; and
- (ii) not less than 15 kilometres per litre of petrol in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1400 cubic centimetres.

by an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (certificate issued in this regard hereinafter referred to as “fuel-efficiency certificate”) on the basis of the tests (hereinafter referred to as the fuel-efficiency test) carried out by the Vehicle Research Development Establishment of the Ministry of Defence, Ahmednagar (Maharashtra), having regard to the following, namely :—

(a) the fuel-efficiency test shall be conducted—

- (i) with a payload of 375 kilograms in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres but not exceeding 1400 cubic centimetres, and
- (ii) with a payload of 450 kilograms in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1400 cubic centimetres;

(b) the fuel-efficiency test shall be conducted using petrol having an octane level not exceeding 87;

(c) the fuel-efficiency test shall be carried out on a selected level test track at a steady speed of 50 kilometres per hour for a minimum stretch of one kilometre and the average of 20 runs, comprising of 10 runs in each direction, shall be taken for carrying out the tests and the test figures shall be corrected to sea level altitude and to plus 25 degree centigrade ambient temperature;

(d) the fuel-efficiency test shall be conducted on five motor cars selected at random by the testing agency from the production plant and the lowest of the test figures shall be relevant for the purpose of issuing fuel-efficiency certificate.

2. The fuel-efficiency certificate so issued shall be valid for a period of six months from the date of issue.

3. Where a manufacturer is entitled for exemption under this notification but is not able to produce a fuel-efficiency certificate at the time of clearance such manufacturer shall undertake to the Assistant Collector of Central Excise that he will produce such fuel-efficiency certificate within a period of eight weeks or such further extended period not exceeding four weeks as may be determined by the Collector of Central Excise and also undertake to pay an amount equal to the difference between the duty leviable but for the exemption contained herein and

that already paid at the time of clearance, if he fails to produce the fuel-efficiency certificate within the said period.

4. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of December, 1988.

अधिसूचना

सं. 502/86-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 1317 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कारों में विनिर्माण के लिए, अपेक्षित संघटकों को (जिनके अन्तर्गत बड़े अवाघात पैक और पूर्णतया अवाघात पैक में ईंधन-दक्ष मोटर कारों के संघटक हैं) :—

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उल्लेख्य सीमाशुल्क से जितना मूल्य के 25 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम में अधिक है; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त प्रतिरिक्त शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :—

(1) इसमें अन्तर्निष्ठ छूट, 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कारों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित केवल उन्हीं संघटकों को (जिनके अन्तर्गत बड़े अवाघात पैक और पूर्णतया अवाघात पैक में ईंधन-दक्ष मोटर कारों के संघटक हैं) लागू होगी जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार से अन्तिम पंक्ति के अधिकारी द्वारा और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संयुक्त सचिव से अन्तिम पंक्ति के अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूचियों के अन्तर्गत आते हैं;

(2) आयातकर्ता, सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उक्त संघटकों का (जिनके अन्तर्गत बड़े अवाघात पैक और पूर्णतया अवाघात पैक में ईंधन-दक्ष मोटर कारों के संघटक हैं) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कारों के विनिर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन ऐसे आयातकर्ता द्वारा आयात किया गया है;

(3) आयातकर्ता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित देशीकरण की डिग्री और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की वास्तविक डिग्री का विस्तृत ब्योरा दशित करने वाला प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है और किसी ऐसे मामले में जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की डिग्री उस डिग्री से निम्न है जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित की गई है वहां आयातकर्ता, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास

विभाग) के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिका-री से प्रमाण-पत्र भी पेश करता है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि देशीकरण की अपेक्षित डिग्री को प्राप्त करने में असफलता विधिमाम्य कारणों की वजह से है जो उसमें लेखबद्ध किए जाएंगे और ऐसी असफलता न्यूनतम है।

- (4) आयातकर्ता ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर से जिसकी अधिकारिता में ऐसी ईंधन-दक्ष मोटर कारों का विनिर्माण करने वाला कारखाना स्थित है, इस आशय का प्रमाण-पत्र पेश करेगा कि ऐसे आयात किए गए संघटकों का 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कारों के विनिर्माण में प्रयोग किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कार” से ऐसी मोटर कार अभिप्रेत है जिसके बारे में अहमदनगर (महाराष्ट्र) स्थित रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान विकास स्थापन द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईंधन-दक्षता परीक्षण कहा गया है) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है (इस संबंध में दिए गए प्रमाण-पत्र को इनमें इसके पश्चात् ईंधन दक्षता प्रमाण-पत्र कहा गया है) कि ऐसी मोटर कार—

- (1) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, प्रति मोटर पेट्रोल में कम से कम 17 किलोमीटर चलेगी;
- (2) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, प्रति मोटर पेट्रोल में कम से कम 15 किलोमीटर चलेगी,

ऐसा करने समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्—

(क) ईंधन-दक्षता परीक्षण—

- (1) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, 375 किलोग्राम आयभार से किया जाएगा, और
- (2) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक ईंधन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, 450 किलोग्राम आयभार से किया जाएगा;

(ख) ईंधन-दक्षता परीक्षण ऐसे पेट्रोल का प्रयोग करके किया जाएगा जिसका आक्टेन लेवल 87 से अधिक नहीं है;

(ग) ईंधन-दक्षता परीक्षण किसी विनिर्दिष्ट लेबल परीक्षण पथ पर कम से कम एक किलोमीटर दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अपरिचालित गति से किया जाएगा और परीक्षण करने के लिए औसतन 20 चक्कर लगाए जाएंगे जिनमें से 10 चक्कर प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण अंक समुद्र तल की ऊंचाई तक और $+25^{\circ}$ से, परिवेश ताप के आधार पर संशोधित किए जाएंगे;

(घ) ईंधन दक्षता परीक्षण, उद्भावन संयंत्र से परीक्षण अभिकर्ता द्वारा सहसा चूमी गई पांच मोटर कारों पर किया जाएगा और परीक्षण अंकों में से न्यूनतम अंक, ईंधन दक्षता प्रमाण-पत्र दिए जाने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा।

2. इस प्रकार दिया गया ईंधन दक्षता प्रमाण-पत्र दिए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमाम्य होगा।

3. जहां आयातकर्ता इस अधिसूचना के अर्धीन टूट का हकदार है किन्तु आयात के समय ईंधन दक्षता प्रमाण-पत्र पेश करने में समर्थ नहीं है वहां ऐसा आयातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को यह सूचना देकर कि वह ऐसा ईंधन दक्षता प्रमाण-पत्र आठ सप्ताह का अवधि के भीतर या चार सप्ताह से अधिक और बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा अवधारित की जाए, पेश करेगा तथा वह इसमें अन्तर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उद्घाटन शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच के अंतर का संभाव करने का भी बचनबंध उस दशा में करेगा जब वह उक्त अवधि के भीतर ईंधन दक्षता प्रमाण-पत्र पेश करने में असफल रहता है।

4. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1988 तक, जिनमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

NOTIFICATION

No. 502/86-CUSTOMS

G.S.R. 1317(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the Public interest so to do, hereby exempts components (including components of fuel efficient motor cars in semi-knocked down packs and completely knocked down packs) required for the manufacture of fuel-efficient motor cars of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres, from :—

- (a) so much of the duty of customs which is leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the amount calculated at the rate of 25 per cent ad valorem; and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the Said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely :—

- (i) the exemption contained herein shall be applicable only to those components (including components of fuel efficient motor cars in semi-knocked down packs and completely knocked down packs) which are covered by lists certified by an officer not below the rank of an Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development and an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) to be required for the manufacture of fuel-efficient motor cars of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres;
- (ii) the importer produces evidence to the Assistant Collector of Customs to the effect that the said components (including components of fuel-efficient motor cars in semi-knocked down packs and completely knocked down packs) have been imported by such importer under a programme duly approved by the Ministry of Industry (Department of Industrial

Development) and the Industrial Adviser or the Additional Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) for the manufacture of fuel-efficient motor cars of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres ;

- (iii) the importer produces a certificate from the Industrial Advisor in the Directorate General of Technical Development showing the details of the degree of indigenisation required to be achieved under the aforesaid programme and the actual degree of indigenisation achieved in the preceding financial year and in a case where the degree of indigenisation achieved in the preceding financial year is lower than the degree as per the approved programme, the importer also produces a certificate from an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) certifying that the failure in achieving the required degree of indigenisation is on account of valid reasons to be recorded in writing and that such failure is marginal ;

- (iv) the importer shall, within such period as the Assistant Collector of Customs may specify in this behalf, produce a certificate from the Assistant Collector of Central Excise in whose jurisdiction the factory manufacturing such fuel-efficient motor cars is situated to the effect that such imported components have been used in the manufacture of fuel-efficient motor cars of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres but not

Explanation :—For the purposes of this notification, “fuel-efficient motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres” means a motor car which is certified to run :—

- (i) not less than 17 kilometres per litre of petrol in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres but not exceeding 1400 cubic centimetres ; and
- (ii) not less than 15 kilometres per litre of petrol in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1400 cubic centimetres,

by an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (the certificate issued in this regard hereinafter referred to as the fuel-efficiency certificate) on the basis of the tests (hereinafter referred to as the fuel-efficiency test) carried out by the Vehicle Research Development Establishment of the Ministry of Defence, Ahmednagar (Maharashtra), having regard to the following, namely :—

- (a) the fuel-efficiency test shall be conducted :—
- (i) with a payload of 375 kilograms in the case of a motor car of engine capacity

exceeding 1000 cubic centimetres but not exceeding 1400 cubic centimetres ; and

- (ii) with a payload of 450 kilograms in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1400 cubic centimetres ;

- (b) the fuel-efficiency test shall be conducted using petrol having an octane level not exceeding 87 ;

- (c) the fuel-efficiency test shall be carried out on a selected level test track at a steady speed of 50 kilometres per hour for a minimum stretch of one kilometre and the average of 20 runs, comprising of 10 runs in each direction, shall be taken for carrying out the tests and the test figures shall be corrected to sea level altitude and to +25°C ambient temperature ;

- (d) the fuel efficiency test shall be conducted on five motor cars selected at random by the testing agency from the production plant and the lowest of the test figures shall be relevant for the purpose of issuing fuel efficiency certificate ;

2. The fuel efficiency certificate so issued shall be valid for a period of six months from the date of issue.

3. Where an importer is entitled for exemption under this notification but is not able to produce a fuel efficiency certificate at the time of importation such importer shall undertake to the Assistant Collector of Customs that he will produce such fuel efficiency certificate within a period of eight weeks or such further extended period not exceeding four weeks as may be determined by the Collector of Customs and also undertake to pay an amount equal to the difference between the duty leviable but for the exemption contained here in and that already paid at the time of importation, if he fails to produce the fuel efficiency certificate within the said period.

4. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of December, 1988.

प्रधिसूचना

सं. 503/86-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 1318 (ब) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक ईंधन क्षमता वाली ईंधन-यन्त्र मोटर कारों के विनिर्माण के लिए प्रयोजित संघटकों को,—

- (क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1973 (1973 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्घाटनीय उतने सीमाशुल्क से जितना मूल्य के 25 प्रतिशत की दर पर संगणित शुल्क से अधिक है ; और

(क) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त प्रतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :

(i) उक्त संघटकों का 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कार के विनिर्माता द्वारा आयात किया जाता है ;

(ii) तकनीकी विकास महाविद्यालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार से अनिवार्य पंक्ति के अधिकारी और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के उप-सचिव से अनिवार्य पंक्ति के अधिकारी का प्रत्येक मामले में यह समाधान हो जाता है और वे यह प्रमाणित करते हैं कि संघटकों का 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कारों के उक्त विनिर्माता द्वारा अपने ग्राहकों को वारंटीव्याप्ति या विजय परभाव सेवा (बाहे मुफ्त या खर्च पर) देने के प्रयोजन के लिए आयात किया गया है ;

(iii) ऐसी ईंधन-दक्ष मोटर कारों का विनिर्माण, उद्योग मंत्रालय द्वारा और उद्योग मंत्रालय के तकनीकी विकास महाविद्यालय के औद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्पन्न रूप में अनुमोदित समर्जित विनिर्माण कार्यक्रम के अधीन किया जाता है और आयातकर्ता, तकनीकी विकास महाविद्यालय के औद्योगिक सलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की द्विती और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त दस्तावेजों की वास्तविक द्विती का विस्तृत ध्वारा पंक्ति करने वाला प्रमाणपत्र पेश करता है और किसी ऐसे मामले में जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त दस्तावेजों की द्विती उस द्विती से निम्न है जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित की गई है वहां आयातकर्ता, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संयुक्त सचिव से अनिवार्य पंक्ति के अधिकारी से प्रमाणपत्र भी पेश करता है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि दस्तावेजों की अपेक्षित द्विती को प्राप्त करने में असफलता विधि मान्य कारणों की वजह से है जो उसमें लेखबद्ध किए जाएंगे और ऐसी असफलता न्यूनतम है ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कार" से ऐसी मोटर कार अभिप्रेत है जिसके बारे में अहमदनगर (महाराष्ट्र) स्थित रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान विकास स्थापन द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईंधन-दक्षता परीक्षण कहा गया है) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संयुक्त सचिव से अनिवार्य पंक्ति के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है, (इस संबंध में दिए गए प्रमाणपत्र को इसमें इसके पश्चात् ईंधन-दक्षता प्रमाणपत्र कहा गया है) कि ऐसी मोटर कार :-

(i) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किंतु 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 17 किलोमीटर चलेगी ; और

(ii) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 15 किलोमीटर चलेगी ;

ऐसा करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :-

(क) ईंधन दक्षता परीक्षण—

(i) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किंतु 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, 375 किलोग्राम भारधार के साथ किया जाएगा ; और

(ii) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, 450 किलोग्राम के साथ किया जाएगा ;

(ख) ईंधन दक्षता परीक्षण ऐसे पेट्रोल का प्रयोग करके किया जाएगा जिसका ग्राइडेन लेवन 87 से अधिक नहीं है ;

(ग) ईंधन दक्षता परीक्षण किसी विशिष्ट लेवन परीक्षण पथ पर कम से कम एक किलोमीटर दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अपरिवर्ती गति में किया जाएगा और परीक्षण करने के लिए प्रयत्न 20 चक्कर लगाए जाएंगे जिसमें से 10 चक्कर प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण अंक समुद्र तल की ऊंचाई तक और $\pm 25^\circ$ सेंटी परितः ताप के आधार पर संशोधित किए जाएंगे, और

(घ) ईंधन दक्षता परीक्षण, उत्पादन संबंध से परीक्षण अधिकता द्वारा सहता चुनी गई पांच मोटर कारों पर किया जाएगा और परीक्षण अंकों में से न्यूनतम अंक, ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा ।

2. इस प्रकार दिया गया ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमार्ग होगा ।

3. जहां आयातकर्ता इस अधिसूचना के अधीन छूट का हकदार किंतु आयात के समय ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में समर्थ नहीं है वहां ऐसा आयातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को यह बचनबद्ध करेगा कि वह ऐसा ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र पाठ सप्ताह की अवधि के भीतर या बार सप्ताह से अधिक और बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा अवधारित की जाए, पेश करेगा तथा वह इसमें अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संघत शुल्क के बीच के अंतर का संदाय करने का भी बचनबद्ध उस दशा में करेगा जब वह उक्त अवधि के भीतर ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहता है ।

4. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1988 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

NOTIFICATION

NO. 503/86-CUSTOMS

G.S.R. 318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts components of fuel-efficient motor cars of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres, from —

(a) so much of the duty of customs which is leviable thereon under the First Schedule

to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the amount calculated at the rate of 25 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :—

(i) that the said components are imported by a manufacturer of fuel-efficient motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres;

(ii) that an officer not below the rank of an Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development and an officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) are satisfied and certify in each case to the effect that the components are imported for the purpose of providing warranty coverage or after sales service (whether free of cost or at a price) by the said manufacturer of fuel-efficient motor cars of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres to their customers;

(iii) that such fuel-efficient motor cars are manufactured under a phased manufacturing programme duly approved by the Ministry of Industry and the Industrial Adviser or the Directorate General of Technical Development in the Ministry of Industry and the importer produces a certificate from the Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development showing the details of the degree of indigenisation required to be achieved under the aforesaid programme and the actual degree of indigenisation achieved in the preceding financial year and in a case where the degree of indigenisation achieved in the preceding financial year is lower than the degree as per the approved programme, the importer also produces a certificate from an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) certifying that the failure in achieving the required degree of indigenisation is on account of valid reasons to be recorded in writing and that such failure is marginal.

Explanation — For the purposes of this notification, “fuel-efficient motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres” means a motor car which is certified to run —

(i) not less than 17 kilometers per litre of petrol in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres but not exceeding 1400 cubic centimetres; and

(ii) not less than 15 kilometers per litre of petrol in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1400 cubic centimetres.

by an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (the certificate issued in this regard hereinafter referred to as fuel efficiency certificate) on the basis of the tests (hereinafter referred to as the fuel-efficiency test) carried out by the Vehicle Research Development Establishment of the Ministry of Defence, Ahmednagar (Maharashtra), having regard to the following, namely :—

(a) the fuel-efficiency test shall be conducted—

(i) with a page of 375 kilograms in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres but not exceeding 1400 cubic centimetres, and

(ii) with a page of 450 kilogram in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1400 cubic centimetres;

(b) the fuel-efficiency test shall be conducted using petrol having an octane level not exceeding 87;

(c) the fuel-efficiency test shall be carried out on a selected level test track at a steady speed of 50 kilometers per hour for a minimum stretch of one kilometer and the average of 20 runs, comprising of 10 runs in each direction, shall be taken for carrying out the tests and the test figures shall be corrected to sea level altitude and +25°C ambient temperature;

(d) the fuel-efficiency test shall be conducted on five motor cars selected at random by testing agency from the production plant and the lowest of the test figures shall be relevant for the purpose of issuing fuel-efficiency certificate.

2. The fuel efficiency certificate so issued shall be valid for a period of six months from the date of issue.

3. Where an importer is entitled for exemption under this notification but is not able to produce a fuel-efficiency certificate at the time of importation such importer shall undertake to the Assistant Collector of Customs that he will produce such fuel-efficiency certificate within a period of eight weeks or such further extended period not exceeding four weeks as may be determined by the Collector of Customs and also undertake to pay an amount equal to difference between the duty leviable but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation, if he fails to produce the fuel-efficiency certificate within the said period.

4. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of December, 1988.

अधिसूचना

सं. 504/86—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 1319(अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1986 (1986 का 23) की धारा 49 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 314/86—सीमाशुल्क, तारीख 13 मई, 1986 में निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

क्रम संख्या 72 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“73. सं. 502—सीमाशुल्क, तारीख 24 दिसम्बर, 1986

74. सं. 503—सीमाशुल्क, तारीख 24 दिसम्बर, 1986”.

NOTIFICATION

NO. 504/86-CUSTOMS

G.S.R. 1319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 49 of the Finance Act, 1986 (23 of 1986), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 314/86 Customs, dated the 13th May, 1986, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Sl. No. 72 and the entry relating thereto the following Sl. Nos. and entries shall be inserted, namely :—

“73. No. 502-Customs, dated the 24th December, 1986

74. No. 503-Customs, dated the 24th December, 1986”.

अधिसूचना

सं. 505/86—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 1320(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की ऐसी प्रत्येक अधिसूचना को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित करती है।

1347 GI/86—2

सारणी

क्र. अधिसूचना सं. और तारीख सं.	संशोधन		
1	2	3	4

1. सं. 29/83—सीमाशुल्क
तारीख 25 फरवरी, 1983

उक्त अधिसूचना में,—

(क) प्रारम्भिक पैरा में,—

(i) खंड (i) और (ii) में,
“भारी उद्योग विभाग” शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, “औद्योगिक विकास विभाग” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ii) के अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा और खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iv) आयातकर्ता, तकनीकी विकास महाविशालय के औद्योगिक सलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए जाने के लिए अतिरिक्त देशीकरण की डिग्री और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की वास्तविक डिग्री का विस्तृत ब्योरा बतित करने वाला प्रमाण पत्र पेश करता है और किसी ऐसे मामले में जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की डिग्री उस डिग्री से कम है जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित की गई है वहां आयातकर्ता, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी से प्रमाणपत्र भी पेश करता है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि देशीकरण की अपेक्षित डिग्री को प्राप्त करने में असफलता विधिमार्ग कारणों की वजह से है जो उसमें लेखबद्ध किए जाएंगे और ऐसी असफलता न्यूनतम है।”;

(iii) स्पष्टीकरण में,—

(क) “(भारी उद्योग विभाग)” कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर “(औद्योगिक विकास विभाग)” कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे तथा “यह प्रमाणित किया जाता है” शब्दों के पश्चात् “(इस संबंध में दिए गए प्रमाण-

1	2	3	1	2	3
		पत्र को इसमें-इसके पश्चात् ईधन दक्षता प्रमाणपत्र कहा गया है) को छूट और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;			(ग) विद्यमान पैरा 2 को पैरा 4 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा ।
	(ख) "या पुणे (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय स्वचालित यंत्र अनुसंधान संगम" शब्द और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;		2. सं. 6/84-सीमाशुल्क, तारीख 10 जनवरी, 1984	उक्त अधिसूचना में,— (क) प्रारंभिक पैरा में,—	
	(ग) खंड (ख) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा और खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—			(i) खंड (i) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;	
	"(घ) ईधन दक्षता परीक्षण, उत्पादन संयंत्र से परीक्षण अधिकर्ता द्वारा सहसा चुनी गई पांच मोटरकारों पर किया जाएगा और परीक्षण अंकों में से न्यूनतम अंक, ईधन दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा ।"			(ii) खंड (ii) में, "भारी उद्योग विभाग" शब्दों के स्थान पर "औद्योगिक विकास विभाग" शब्द रखे जाएंगे ;	
	(ख) पैरा 1 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएंगे, अर्थात्:—			(iii) खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—	
	"2. इस प्रकार दिया गया ईधन दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमार्ग होगा ।			"(iii) ऐसी ईधन-दक्ष मोटर कारों का विनिर्माण, उद्योग मंत्रालय द्वारा और उद्योग मंत्रालय के तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित सर्व-जित विनिर्माण कार्यक्रम के अधीन किया जाता है और आयातकर्ता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम के अर्जन प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित देशीकरण की डिग्री और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की वास्तविक डिग्री का विस्तृत स्वीरा दशित करने वाला प्रमाणपत्र पेश करता है और किसी ऐसे मामले में जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की डिग्री, उक्त डिग्री से निम्न है जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित की गई है वहां आयातकर्ता, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी से प्रमाणपत्र भी पेश करता है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि देशीकरण की अपेक्षित डिग्री को प्राप्त करने में असफलता विधिमार्ग कारणों की वजह से है जो उनमें से लेखाबद्ध किए जाएंगे और ऐसी अवकलना न्यूनतम है ।"	
	3. जहां आयातकर्ता इस अधिसूचना के अधीन छूट का हकदार है किन्तु आयात के समय ईधन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में समर्थ नहीं है वहां ऐसा आयातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को यह बचनबंध करेगा कि वह ऐसा ईधन दक्षता प्रमाणपत्र आठ सप्ताह की अवधि के भीतर या चार सप्ताह से अधिक और बाढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा अवधारित की जाए, पेश करेगा तथा वह इसमें अंतर्निष्ठ छूट के न दिए जाने की वशा में उन्मुखणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संवत् शुल्क के बीच के अंतर का संदाय करने का भी बचनबंध उस वशा में करेगा जब वह उक्त अवधि के भीतर ईधन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहता है ।"				

3

2

3

1

3

3

(iv) स्पष्टीकरण में :—

(क) "(भारी उद्योग विभाग)" कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर "(औद्योगिक विकास विभाग कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे तथा "यह प्रमाणित किया जाता है" शब्दों के पश्चात् (इस संबंध में दिए गए) प्रमाणपत्र को इसमें इसके पश्चात् ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र कहा गया है) कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) "या पुने (महाराष्ट्र स्थित भारतीय स्वचालित यंत्र अनुसंधान संगम" शब्द और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

(ग) खंड (ख) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा और खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) ईंधन दक्षता परीक्षण, उत्पादन संयंत्र से परीक्षण अभिकर्ता द्वारा महत्वा कुनी गई पांच मोटर कारों पर किया जाएगा और परीक्षण अंकों में से न्यूनतम अंक, ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा।"

(ख) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"2. इस प्रकार दिया गया ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र] दिए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

3 जहाँ आयातकर्ता इस अधिसूचना के अधीन छुट का हकदार है किंतु आयात के समय ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में समय नहीं है वहाँ ऐसा आयातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को यह बचनबंध करेगा कि वह ऐसा ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र माठ माताह की अवधि के भीतर या चार माताह स अनधिक और बड़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा अवधारित की जाए, पेश करेगा तथा वह इसमें अंतर्विष्ट छुट के न दिए

जाने की दशा में उपग्रहीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संवत् शुल्क के बीच के अंतर का संदाय करने का भी बचनबंध उस दशा में करेगा जब वह उक्त अवधि के भीतर ईंधन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहता है।

4 यह अधिसूचना 24 फरवरी, 1988 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

3 नं. 254/84—सीमाशुल्क,

तारीख 8 अक्टूबर, 1984

उक्त अधिसूचना में,

(क) प्रारंभिक पैरा में,—

(i) "ऐसी समता वाली ईंधन-दक्ष मोटर कार जिसकी इंजन क्षमता 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से अधिक न हो" शब्द और अंकों के स्थान पर "ईंधन दक्ष मोटर कार" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (i) और (ii) में, "भारी उद्योग मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते हैं "औद्योगिक विकास विभाग" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ii) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा और खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) आयातकर्ता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक मालाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित दैनिकीकरण की डिप्री और पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त दैनिकीकरण की वास्तविक डिप्री का बिस्तृत और दक्षित करने वाला प्रमाणपत्र पेश करता है और किसी ऐसे मामले में जहाँ पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त दैनिकीकरण की डिप्री, उस डिप्री से निम्न है जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित की गई है वहाँ आयातकर्ता, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संयुक्त सचिव से अनिमित्त पंक्ति के अधिकारी से प्रमाणपत्र भी पेश करता है जिसमें

1	2	3	1	2	3
		यह प्रमाणित किया गया हो कि देशीकरण की अपेक्षित डिग्री की प्राप्ति करने में असफलता विधिमार्ग कारणों की वजह से है जो उसमें लेखबद्ध किए जाएंगे और ऐसी असफलता न्यूनतम है”;			(iii) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक ईंधन क्षमता वाली मोटर कार की वशा में, 450 आयुवार के साथ किया जाएगा”;
	(iv) स्पष्टीकरण में,				(v) खंड (ख) के अंत में आने वाले “और” शब्द का जोड़ दिया जाएगा और खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
	(क) (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—				“(घ) ईंधन दक्षता परीक्षण, उद्घाटन संयंत्र से परीक्षण अभिकर्ता द्वारा सहसा चुनी गई पांच मोटर कारों पर किया जाएगा और परीक्षण अंकों में से न्यूनतम अंक, ईंधन क्षमता प्रमाणपत्र दिए जाने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा।”;
	“(ii) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक ईंधन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 17 किलोमीटर चलेगी; और				(ख) पैरा 1 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
	(iii) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक ईंधन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में, प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 15 किलोमीटर चलेगी”;				“2. इस प्रकार दिया गया ईंधन क्षमता प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख से छह माह की अवधि के लिए विधिमार्ग होगा।
	(ख) “(भारी उद्योग विभाग)” कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर “(औद्योगिक विकास विभाग)” कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे तथा “संयुक्त सचिव ने अतिरिक्त पंक्ति के अधिकारी द्वारा” शब्दों के पश्चात् “यह प्रमाणित किया जाता है (इन संबंध में दिए गए प्रमाणपत्र को इसमें इसके पश्चात् ईंधन क्षमता प्रमाणपत्र कहा गया है) कि मोटर कार” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे:				3. जहां आयुक्तकर्ता दत्त अधिसूचना के अधीन छूट का हकदार है किन्तु आयुक्त के समय ईंधन क्षमता प्रमाणपत्र पेश करने में समर्थ नहीं है, वहां ऐसा आयुक्तकर्ता, सहायक सीमांतक कलक्टर को यह बतलाना करेगा कि वह ऐसा ईंधन क्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त सप्ताह की अवधि के भीतर या बार सप्ताह से अधिक और बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर भी सीमांतक कलक्टर द्वारा अवधारित की जाए, पेश करेगा तथा वह इसमें अतिरिक्त छूट के त दिए जाने की वशा में उद्घाटनीय गुरु और आयुक्त के समय पहले ही सदस्त गुरु के बीच के अंत का संवाप करने का भी अवसर उस दशा में करेगा जब वह उक्त अवधि के भीतर ईंधन क्षमता प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहता है।”;
	(ग) “या पुणे (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय स्वचालित यंत्र अनुसंधान संगम” शब्द और कोष्ठकों का जोड़ दिया जाएगा।				(ग) विनियमन पैरा 2 को पैरा 4 के रूप में पुनः संशोधित किया जाएगा।
	(घ) खंड (क) में, उपखंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—				
	“(ii) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक ईंधन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में 375 किलो-ग्राम भार के साथ किया जाएगा, और				

[फा. सं. 315/89/86 पी. एच. ए.]

गीतम रे, उप सचिव

NOTIFICATION

NO. 505/86-CUSTOMS

GSR. 1320 (F).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (51 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No. Notification No. and date		Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 29/83-Customs, dated the 25th February, 1983.	<p>In the said notification,—</p> <p>(a) in the opening paragraph,—</p> <p>(i) in clauses (i) and (ii), for the words "Department of Heavy Industry" wherever they occur, the words "Department of Industrial Development" shall be substituted;</p> <p>(ii) in clause (ii), the word "and" occurring at the end shall be omitted, and after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :—</p> <p>"(iv) the importer produces a certificate from the Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development showing the details of the degree of indigenisation required to be achieved under the aforesaid programme and the actual degree of indigenisation achieved in the preceding financial year and in a case where the degree of indigenisation achieved in the preceding financial year is lower than the degree, as per the approved programme, the importer also produces a certificate from an officer not below the rank of a Joint secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) certifying that the failure in achieving the required degree of indigenisation is on account of valid reasons to be recorded in writing and that such failure is marginal.";</p> <p>(iii) in the Explanation,—</p> <p>(a) for the words and brackets "(Department of Heavy Industry)", the brackets and words "(Department of Industrial Development) (certificate issued in this regard hereinafter referred to as fuel efficiency certificate)" shall be substituted;</p>

(1) (2)

(3)

(b) the words and brackets "or the Automotive Research Association of India, Pune (Maharashtra)" shall be omitted;

(c) in clause (b), the word "and" occurring at the end shall be omitted, and after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

"(d) the fuel efficiency test shall be conducted on five motor cars selected at random by the testing agency from the production plant and the lowest of the test figures shall be relevant for the purpose of issuing fuel efficiency certificate.";

(b) after paragraph 1, the following paragraphs shall be inserted, namely :—

"2. The fuel efficiency certificate so issued shall be valid for a period of six months from the date of issue.

3. Where an importer is entitled for exemption under this notification but is not able to produce a fuel efficiency certificate at the time of importation such importer shall undertake to the Assistant Collector of Customs that he will produce such fuel efficiency certificate within a period of eight weeks or such further extended period not exceeding four weeks as may be determined by the Collector of Customs and also undertake to pay an amount equal to the difference between the duty leviable but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation, if he fails to produce the fuel efficiency certificate within the said period.";

(c) the existing paragraph 2 shall be renumbered as paragraph 4.

2. No. 6/84-Customs, dated the 10th January, 1984.

In the said notification,—

(a) in the opening paragraph,—

(i) in clause (i), the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(ii) in clause (ii), for the words "Department of Heavy Industry" the words "Department of Industrial Development" shall be substituted;

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		<p>(iii) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely—</p> <p>“(iii) that such fuel efficient motor cars are manufactured under a phased manufacturing programme duly approved by the Ministry of Industry and the Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development in the Ministry of Industry and the importer produces a certificate from the Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development showing the details of the degree of indigenisation required to be achieved under the aforesaid programme and the actual degree of indigenisation achieved in the preceding financial year and in a case where the degree of indigenisation achieved in the preceding financial year is lower than the degree as per the approved programme, the importer also produces a certificate from an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), certifying that the failure in achieving the required degree of indigenisation is on account of valid reasons to be recorded in writing and that such failure is marginal.”</p>			<p>(b) for paragraph 2, the following paragraphs shall be inserted, namely :—</p> <p>“2. The fuel efficiency certificate so issued shall be valid for a period of six months from the date of issue.</p> <p>3. Where an importer is entitled for exemption under this notification but is not able to produce a fuel-efficiency certificate at the time of importation such importer shall undertake to the Assistant Collector of Customs that he will produce such fuel-efficiency certificate within a period of eight weeks or such further extended period not exceeding four weeks as may be determined by the Collector of Customs and also undertake to pay an amount equal to the difference between the duty leviable but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation, if he fails to produce the fuel-efficiency certificate within the said period.</p> <p>4. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 24th day of February, 1988.”</p>
		<p>(iv) in the Explanation,—</p> <p>(a) for the words and brackets “(Department of Heavy Industries)”, the brackets and words “(Department of Industrial Development) (certificate issued in this regard hereinafter referred to as the fuel efficiency certificate)” shall be substituted;</p> <p>(b) the words and brackets “or the Automotive Research Association of India, Pune (Maharashtra)” shall be omitted</p> <p>(c) in clause (b), the word “and” occurring at the end shall be omitted and after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—</p> <p>“(d) The fuel-efficiency test shall be conducted on five motor cars selected at random by the testing agency from the production plant and the lowest of the test figures shall be relevant for the purpose of issuing the fuel efficiency certificate.”;</p>	<p>3. No. 254/84- Customs, dated 8th October, 1984</p>		<p>In the said notification,—</p> <p>(a) in the opening paragraph,—</p> <p>(i) the words and figures “of engine capacity not exceeding 1000 cubic centimetres” shall be omitted;</p> <p>(ii) in clauses (i) and (ii), for the words “Department of Heavy Industry”, wherever they occur, the words “Department of Industrial Development” shall be substituted;</p> <p>(iii) in clause (ii), the word “and” occurring at the end shall be omitted, and after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :—</p> <p>“(iv) the importer produces a certificate from the Industrial Adviser in the Directorate General of Technical Development showing the details of the degree of indigenisation required to be achieved under the aforesaid programme and the actual degree of indigenisation achieved in the preceding financial year and in a case where the degree of indigenisation achieved in the preceding financial year is lower than the degree as per the approved</p>

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		programme, the importer also produces a certificate from an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) certifying that the failure in achieving the required degree of indigenisation is on account of valid reasons to be recorded in writing and that such failure is marginal.”;			(v) in clause (b), the word, “and” occurring at the end shall be omitted and after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—
		(iv) in the Explanation,—			“(d) the fuel-efficiency test shall be conducted on five motor cars selected at random by the testing agency from the production plant and the lowest of the test figures shall be relevant for the purpose of issuing fuel efficiency certificate.”;
		(a) after clause (i), the following clauses shall be inserted, namely :—			(b) after paragraph 1, the following paragraphs shall be inserted, namely :—
		“(ii) not less than 17 kilometres per litre of petrol in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres but not exceeding 1400 cubic centimetres; and			“2. The fuel-efficiency certificate so issued shall be valid for a period of six months from the date of issue.
		(iii) not less than 15 kilometres per litre of petrol in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1400 cubic centimetres.”			3. Where an importer is entitled for exemption under this notification but is not able to produce fuel-efficiency certificate at the time of importation such importer shall undertake to the Assistant Collector of Customs that he will produce such fuel-efficiency certificate within a period of eight weeks or such further extended period not exceeding four weeks as may be determined by the Collector of Customs and also undertake to pay an amount equal to the difference between the duty leviable but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation if he fails to produce the fuel efficiency certificate within the said period.”;
		(b) for the words and brackets “(Department of Heavy Industry)”, the words and brackets “(Department of Industrial Development) (certificate issued in their regard hereinafter referred to as the fuel efficiency certificate)” shall be substituted;			(c) the existing paragraph 2 shall be renumbered as paragraph 4.
		(c) the words and brackets “or the Automotive Research Association of India, Pune (Maharashtra)” shall be omitted;			
		(d) in clause (a), after sub-clause (i), the following sub-clauses shall be inserted, namely :—			
		“(ii) with a payload of 375 kilograms in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1000 cubic centimetres but not exceeding 1400 cubic centimetres; and			
		(iii) with a payload of 450 kilograms in the case of a motor car of engine capacity exceeding 1400 cubic centimetres;”;			

[F. No. 346/89/86-TRU]

GAUTAM RAY, Dy. Secy.

